क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	होम गार्डों की प्राधिकृत संख्या	होम गार्डों की स्थापित संख्या
23.	उड़ीसा	16362	11425
24.	पांडिचेरी (संघ शासित)	440	290
25.	पंजाब	34595	34151
26.	राजस्थान	28050	27145
27.	सिक्किम	546	546
28.	तमिलनाडु	11622	9746
29.	त्रिपुरा	4207	2773
30.	उत्तर प्रदेश	123420	119706
31.	पश्चिम बंगाल	46750	22704

पूर्वोत्तर में गैर-आदिवासी हिंदुओं और मुसलमानों की समस्याएं

833. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेषकर मेघालय में गैर-आदिवासियों, हिन्दुओं और मुस्लिमों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारणा) अधिनियम, 1993 के प्रस्तावित निरसन के संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने, 4.2.1999 को प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान, असम और मेघालय में अल्पसंख्यकों को सामने आ रही समस्याओं के बारे में उन्हें मौखिक रूप से बताया था। तथापि, इस संबंध में आयोग द्वारा केन्द्र या संबंधित राज्य सरकारों को कोई लिखित रिपोर्ट नहीं भेजी गई है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, द्वितीय सांविधिक आयोग (नवम्बर, 1996, नवम्बर, 1999) कार्यालय में दो वर्ष का काल" उपलब्धियां और असफलताएं, भावी योजनाएं और देश में वर्तमान अल्पसंख्यक स्थिति का मूल्यांकन नामक दस्तावेज की एक प्रति प्रधान मंत्री को भी भेजी है। इस रिपोर्ट में आयोग ने राज्य स्तरीय अल्पसंख्यक अवधारणा और हिन्दुओं को अल्पसंख्यकों के रूप में मानने जो जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड राज्यों और संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप में हिन्दुओं को अल्पसंख्यकों के रूप में मानने और अपने क्षेत्राधिकार को पाने की हकदारी का उल्लेख किया है।

(ग) आई०एस०(डी०टी०) अधिनियम, 1993 को निरस्त करने का प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

Organisations Receiving Foreign Funds

834. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total amount of funds received from foreign countries during the last three years and till date by religious, social and volutary organisations functioning in the country, year-wise; and

(b) whether such organisations have so far intimated to Government about the receipt/utilisation of said funds by them in the country?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) and (b) According to the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976, associations having a definite cultural, economic, educational, religious or social programme can accept foreign contribution only after they are granted

registration/prior permission to receive such foreign contribution by the Central Government.

Details of foreign contribution received & utilised by such voluntary associations are contained in the Annual Report brought out by the Ministry of Home Affairs (Foreigners Division). Copies of the Annual Report (upto 1996-97) are available in the Parliament Library. The Annual Report for 1997-98 is being compiled. These reports are based on returns submitted by these associations under the Act.

Rise of Guerrilla groups

835. SHRI NARENDRA MOHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are taking necessary steps to control the rise of growing guerrilla groups in the country;

(b) the States which have been under the influence of caste war and the revolutionary naxalities; and

(c) what action has been taken by Government to control the rise of these groups where criminals and extortionists are leading to massacres and killings of the poor?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) Yes Sir.

(b) The States of Bihar, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu have come to notice for caste-based clashes. The States mainly affected by naxalite activities are Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra and Orissa.

(c) Central Government has taken various measures to help the States to fight the naxalite menace. These include holding of coordination meetings with the States concerned as well as with the various intelligence and investigating agencies of the Central Government. In certain special circumstances, financial assistance has also been given to some of the affected States over and above the on-going allocation for modernisation of police and supply of weapons. Training of police personnel in anti-extremist operations has also been arranged. Central Government, in consultation with the concerned States, has drawn up an Action Plan in this regard.

State Governments have been requested to take immediate steps to implement the Action Plan. Action taken by the States is being reviewed from time to time. A Coordination Centre has also been set up on 26.6.1998. This Centre is Chaired by the Union Home Secretary and has representatives of the concerned State Governments as it Members.

There have been several instances of clashes between the private Senas and the Left Wing Extremists in Bihar. While the Central Government is providing financial assistance for modernisation of police, 'Public Order' being a State subject, it is the responsibility of the concerned State Governments to maintain law and order in the States.

सामाजिक क्रियाकलापों में लगे संस्थानों के लिये विदेशी चंदा

836. श्री कपिल सिब्बल:
श्री राज मोहिन्दर सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सामाजिक क्रियाकलापों में लगे संस्थानों को विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थानों के नाम क्या हैं जिन्होंने चालू वर्ष में जनवरी, 1999 के अंत तक विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त की और प्रत्येक संस्थान द्वारा अलग-अलग विदेशों से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त की गई; और

(ग) देश में यह संस्थान किन जगहों पर कार्यरत हैं तथा इनका कार्य-क्षेत्र क्या है और इन संस्थानों के क्रियाकलापों में कौन-कौन से क्षेत्र शामिल हैं?